भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3

7 दिसम्बर, 2022 को उत्तरार्थ

ग्राम स्तर पर सहकारी समितियां

3# श्रीमती गीता उर्फ चन्द्रप्रभा:

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या प्रत्येक ग्राम स्तर पर सहकारी समितियां गठित करने की कोई योजना है;
- (ख) क्या इन सहकारी समितियों के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं; और
- (ग) यदि हां, तो उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनमें ये सहकारी समितियां अपना कार्य करने में सक्षम होंगी?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क): जी, महाशय। देश में 2,55,643 पंचायतों और 6,62,750 गाँवों के विरुद्ध लगभग 95,000 प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियां (PACS); 1,99,182 प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियां और 25,297 प्राथमिक मात्स्यिकी समितियां हैं। कार्य आबंटन नियम, 1961 के अनुसार, मंत्रालय के अधिदेशों में से एक "देश में सहकारिता आंदोलन को सुदृढ़ बनाना तथा सबसे निचले स्तर तक इसकी पहुंच बनाना" है।

(ख) और (ग): नई सहकारी समितियों को अपनी रोजमर्रा के कार्यों को करने के लिए अतिरिक्त श्रमबल की आवश्यकता होगी जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय द्वारा सभी हितधारकों के साथ विस्तृत परामर्श करने के पश्चात, राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों को उनके संबंधित राज्य सहकारी समिति अधिनियमों के अनुसार अपनाने हेतु, प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स) के लिए मॉडल उपविधियां तैयार की गई हैं। पैक्स के ये आदर्श उपनियम उन्हें डेयरी, मत्स्य पालन, फूलों की खेती, गोदामों की स्थापना, खाद्यान्न, उर्वरक, बीज, एलपीजी/पेट्रोल/सीएनजी वितरण एजेंसी, बैंकिंग प्रतिनिधि, सामान्य सेवा केंद्र जैसी 25 से अधिक व्यावसायिक गतिविधियों को करने में सक्षम बनाएंगे। पैक्स की गतिविधियों में वृद्धि के साथ, वे पूरे देश में पंचायत/ग्राम स्तर पर रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करने में सक्षम होंगे।